नईदुनिया

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता समिति की बैठक नई दिल्ली में संपन्न

एआईटीआईजीए संयुक्त समिति की छठी बैठक नई दिल्ली में हुई आयोजित

नई दिल्ली

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) संयुक्त समिति की छठी बैठक राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक में नेताओं ने 2025 तक वार्ता पूरी करने के लिए शीघ्र समीक्षा प्रक्रिया का आग्रह किया। ये बैठक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित की गई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि एआईटीआईजीए संयुक्त समिति की 21 से 22 नवंबर तक चली दो दिवसीय बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल और मलेशिया के निवेश, व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय की उप-महासचिव (व्यापार) मस्तूरा अहमद मुस्तफा ने की। बैठक में भारत और सभी 10 आसियान सदस्य देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंत्रालय के मुताबिक एआईटीआईजीए समीक्षा वार्ता के इस दौर से पहले दो उच्च स्तरीय बैठकें हुई थीं, जिसमें सितंबर 2024 में 21वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक और अक्टूबर 2024 में 21वीं आसियान-भारत शिखर बैठक शामिल हैं। ये दोनों बैठक वियनतियाने लाओस में हुई थी। उल्लेखनीय है कि आसियान एक समूह के तौर पर भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक है, जिसकी भारत के वैश्विक व्यापार में करीब 11 फीसदी हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 121 अरब डॉलर था, जो अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान 5.2 फीसदी की वृद्धि के साथ 73 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया।

न्यूज ब्रीफ

गुजरात के जीएसटी विभाग ने 3.53 करोड़ की कर चोरी पकड़ी, कंपनियां वास्तविक आय को छिपा रही थीं

अहमदाबाद । गुजरात राज्य जीएसटी विभाग ने सात वाणिज्यिक संस्थाओं की तलाशी के दौरान 3.53 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया। एक अधिकारी ने कहा कि ये कंपनियां वास्तविक आय को छिपा रही थीं, बिना चालान के बिक्री कर रही थीं और कर देनदारी को कम करके दिखा रही थीं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्य में उपभोक्ताओं के साथ लेनदेन करने वाली संस्थाओं (बी2सी) द्वारा माल और सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की आशंका में सात परिसरों में तलाशी ली गई थी। बयान में कहा गया कि इन फर्मों में अहमदाबाद के दो बैटरी डीलर, डांग जिले के वाघई में चार तंबाकू डीलर और नाडियाड के खेड़ा शहर में एक सैलून शामिल हैं।

आईआईएफसीएल की 60 करोड़ डॉलर जुटाने एडीबी, कोरियाई बैंक से चल रही बातचीत

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और कोरियाई एक्जिम बैंक के साथ बातचीत कर रही है। आईआईएफसीएल ने कहा कि वह इस राशि का इस्तेमाल अपने निवेशक आधार को बढ़ाने और उधार लेने की लागत कम करने के लिए करेगी। आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक पीआर जयशंकर ने यहां निवेशक सम्मेलन में कहा कि बातचीत अग्रिम चरण में है और समझौते पर दिसंबर में हस्ताक्षर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईआईएफसीएल एक बार में पूरे 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर उधार लेने की इच्छुक है। हालांकि इतनी धनराशि की उपलब्धता उधार देने वाली एजेंसी पर निर्भर है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 20 करोड़ करोड़ डॉलर आ सकते हैं और बाकी राशि 2025-26 में आएगी ।

भारतीयों को ब्रांड भारत बनाने पश्चिम के फरमानों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिएः सीतारमण

बेंगलुरु । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव 2024 में कहा कि अगर हम 'ब्रांड भारत' बनाना चाहते हैं, तो हमें सही क्या है, इस बारे में पश्चिम के फरमानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हजारों साल से वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, शोषण की बात कभी नहीं उठी और अचानक एक पारंपरिक उद्योग जैसे, मान लीजिए, कालीन बनाने के काम के लिए, आपको पश्चिम के खरीदारों से एक फरमान आया कि आप इन कालीनों को बनाने के लिए बच्चों का उपयोग कर रहे हैं। हम इसे आपसे नहीं खरीदेंगे। सीतारमण ने कहा कि भारत में परिवार बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित किए बिना शिल्पकार बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक शिल्प बहुत कम उम्र में नहीं सीखा जाता है, एक शिल्पकार कभी इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता। ऐसे में हमें खड़े होकर कहना होगा कि हम उनकी शिक्षा का ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर नैतिक उत्पादन के लिए जिस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, वे हमारी तरफ से अपने आप होने चाहिए, न कि पश्चिमी फरमानों के जारी होने के बाद किए जाने चाहिए। सीतारमण ने यह भी कहा कि हमारे मंदिरों और हमारे प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का महत्व अभी की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। लोगों को यह बताने की जरूरत है कि प्राचीन काल से ही विज्ञान में भारत की ताकत अटूट रही है। सीतारमण ने कहा कि भारत के पास सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों की बदौलत ज्ञान का समृद्ध भंडार है। ये प्राचीन भारत के ब्रांड हैं, जिनका हम आज भी उल्लेख करते हैं।

सेंसेक्स और निफ्टी में सप्ताह भर रही तेजी, सेंसेक्स 79,117 पर और निफ्टी 23,907 पर बंद

मुंबई

इस सप्ताह बैंकिंग शेयरों में खरीदारी, आईटी इंडेक्स में तेजी और एफएमसीजी इंडेक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू बैंक शेयरों में खरीदारी की वजह से शेयर बाजार में तेजी देखी गई। बुधवार 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वजह से घरेलू शेयर बाजार में कारोबार नहीं हुआ, जिससे इस सप्ताह केवल चार दिन ही शेयर बाजार खुले रहे। विदेशी फंडों की लगातार निकासी, आईटी शेयरों में बिकवाली और अमेरिकी बाजारों से कमजोर संकेत के कारण सोमवार को शुरुआती कारोबार में इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक फिर फिसल गए। बीएसई सेंसेक्स 511 अंक गिरकर 77,058 पर खुला और 241.30 अंक गिरकर 77,339.01 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 50 162 अंक गिरकर 23,370 पर खुला और 78.90 अंक गिरकर 23,453.80 पर बंद हुआ। मंगलवार को बेंचमार्क सूचकांकों में तेजी से उछाल आया और सात सत्रों की गिरावट थम गई, इस दौरान एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 1044.89 अंक बढ़कर 78,383.90 पर खुला और 239.38 अंक की बढ़त के साथ 77,578.38 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 50 304.50 अंक बढ़कर 23,758.30 पर खुला और 64.70 अंक की बढ़त के साथ 23,518.50 अंक पर बंद हुआ। अदाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट और विदेशी फंड के निरंतर निकासी के बीच गुरुवार को शुरुआती कारोबार में इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में बीएसई का सेंसेक्स 468.17 अंक गिरकर 77,110.21 अंक पर खुला और 422.59 अंक गिरकर 77,155.79 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 179.75 अंक गिरकर 23,338.75 अंक पर खुला और 168.60 अंक गिरकर 23,349.90 पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों से मिलेजुले संकेतों के बावजूद सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सुबह की शुरुआत में सेंसेक्स 750 अंक की तेजी के साथ 77,920 के स्तर पर खुला और 1,961.32 अंक चढ़कर 79,117.11 पर बंद हुआ। निफ्टी 230 अंक तेज होकर 23,580 के स्तर पर खुला और 23,900 अंकों के पार 557.35 अंकों की बढ़त के साथ 23,907.25 पर बंद हुआ।

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 17.76 अरब डॉलर की गिरावट, पिछले सप्ताह यह भंडार 6.47 अरब डॉलर घटकर 675.65 अरब डॉलर था

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त सप्ताह में 17.76 अरब डॉलर घटकर 657.89 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। पिछले सप्ताह यह भंडार 6.47 अरब डॉलर घटकर 675.65 अरब डॉलर था। सितंबर के अंत में भंडार 704.88 अरब डॉलर के उच्चस्तर पर था, फिर से उसमें पिछले कई हफ्तों से गिरावट आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां भी 15.55 अरब डॉलर घटकर 569.83 अरब डॉलर रहीं। इसमें उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियां शामिल हैं, जिनमें यूरो, पाउंड, और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राएं होती हैं। साथ ही स्वर्ण भंडार का मूल्य भी 2.07 अरब डॉलर घटकर 65.75 अरब डॉलर रहा और विशेष आहरण अधिकार 9.4 करोड़ डॉलर घटकर 18.06 अरब डॉलर पर रहा। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार भी 5.1 करोड़ डॉलर घटकर 4.25 अरब डॉलर पर आ गया। इन आंकड़ों की छठे संख्याक चिह्न है, जो देश की विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति को दर्शाते हैं।

टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत केंद्र सरकार अपनी किसी एजेंसी के माध्यम से टेलीकॉम कंपनियों से ट्रैफिक डेटा या अन्य डेटा की मांग कर सकती है। यह डेटा संदेशों के कंटेंट के अलावा अन्य किसी फॉर्मेट में हो सकता है और इसे स्टोर और प्रोसेस करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की स्थापना की जा सकती है। नए नियमों के अनुसार जिन एजेंसियों को डेटा इकट्ठा करने का अधिकार मिलेगा, उन्हें इसे गोपनीय तरीके से स्टोर करना होगा।

इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को एक साइबर पॉलिसी अपनानी होगी, जिसमें सिक्योरिटी से संबंधित रिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्क टेस्टिंग, ट्रेनिंग और रिस्क असेसमेंट जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी। टेलीकॉम कंपनियों को अब चीफ टेलिकम्युनिकेशंस सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। इस अधिकारी का काम सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के दौरान तत्काल उपाय करना होगा। सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना को केंद्र सरकार को 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही घटना की विस्तृत जानकारी जैसे पीड़ित यूजर्स की संख्या, स्थान और घटनाओं का असर भी 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना होगा। नए नियमों के तहत भारत में बने या आयात किए गए सभी फोन डिवाइस का आईएमईआई नंबर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य फर्जी डिवाइस और अवैध गतिविधियों को रोकना है।

जिन एजेंसियों को डेटा इकट्ठा करने का अधिकार मिलेगा, उन्हें इसे गोपनीय तरीके से स्टोर करना होगा

अब फ्लाइट में देरी होने पर यात्रियों को मिलेगी राहत, यात्रियों को विमान में बैठे रहने की बाध्यता नहीं होगी

नई दिल्ली

सर्दियों में उत्तर भारत में कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स समय पर उड़ान नही भर पाती है। इसलिए अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने यात्रियों की इन समस्याओं को कम करने के लिए एयरलाइंस पर सख्ती बढ़ा दी है। फ्लाइट डिले की स्थिति में यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए के निर्णय की जानकारी साझा की। निर्देशों के अनुसार नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने यात्रियों के लिए एक और बड़ी सुविधा दी है। यदि तकनीकी कारणों या खराब मौसम के कारण फ्लाइट में देरी होती है, तो यात्रियों को विमान में बैठे रहने की बाध्यता नहीं होगी। वे एयरपोर्ट पर आराम से इंतजार कर सकते हैं और फ्लाइट तैयार होने पर दोबारा विमान में चढ़ सकेंगे।

डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट पर 3496 ग्राम कोकीन के साथ एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया

मुंबई/नई दिल्ली

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने एक बड़ी कार्रवाई में मुंबई एयरपोर्ट पर 3496 ग्राम कोकीन के साथ एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इस कोकीन का अवैध बाजार में अनुमानित मूल्य करीब 34.96 करोड़ रुपये है।

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि एक राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने 22 नवंबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिएरा लियोन से आने वाले एक लाइबेरिया के नागरिक को पकड़ा। यात्री के ट्रॉली बैग की जांच के दौरान डीआरआई अधिकारियों ने पाया कि यह असामान्य रूप से भारी था, जिसकी गहन जांच में दो पैकेट मिले, जिनमें एक सफेद पाउडर जैसा पदार्थ था, जिसे ट्रॉली बैग के नकली तल में बड़ी चालाकी से छिपाया गया था।

डीआरआई के अनुसार फील्ड परीक्षणों से पुष्टि हुई कि यह पदार्थ कोकीन था, जिसका कुल वजन 3496 ग्राम था, जिसका अनुमानित अवैध बाजार मूल्य करीब 34.96 करोड़ रुपये है। उस यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। एजेंसी ने कहा कि आगे की जांच जारी है। डीआरआई नशीले पदार्थों की तस्करी के सिंडिकेट को खत्म करने और हमारे नागरिकों को नशीले पदार्थों के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिंद्रा लाइफस्पेस की इकाई सुमितोमो चेन्नई औद्योगिक पार्क में करेगी 225 करोड़ का निवेश

औद्योगिक पार्क वर्तमान में 307 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है

नई दिल्ली

रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी और जापान सुमितोमो कॉरपोरेशन तमिलनाडु में अपनी मौजूदा औद्योगिक पार्क परियोजना के विस्तार के लिए करीब 225 करोड़ रुपये निवेश करेंगी। औद्योगिक पार्क वर्तमान में 307 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें वैश्विक और घरेलू कंपनियां अपनी औद्योगिक सुविधाएं स्थापित कर रही हैं। महिंद्रा लाइफस्पेस ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसकी अनुषंगी कंपनी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लिमिटेड (एमडब्ल्यूसीडीएल), सुमितोमो कॉरपोरेशन और महिंद्रा इंडस्ट्रियल पार्क चेन्नई लिमिटेड (एफआईपीसीएल) ने तमिलनाडु में मौजूदा औद्योगिक पार्क के विस्तार के लिए एक 'पूरक संयुक्त उद्यम समझौता' किया है। महिंद्रा इंडस्ट्रियल पार्क चेन्नई लिमिटेड (एफआईपीसीएल), एमडब्ल्यूसीडीएल की अनुषंगी कंपनी है। महिंद्रा लाइफस्पेस के पास एमडब्ल्यूसीडीएल में 89 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) के पास शेष 11 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा एमडब्ल्यूसीडीएल के पास एमआईपीसीएल में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष 40 प्रतिशत हिस्सेदारी सुमितोमो कॉरपोरेशन (जापान) के पास है। कंपनी सूचना के अनुसार संयुक्त उद्यम साझेदारों यानी एमआईपीसीएल के शेयरधारकों ने परियोजना के विकास के लिए करीब 225 करोड़ रुपये निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। पूंजी निवेश संयुक्त उद्यम साझेदारों की मौजूदा शेयरधारिता के अनुसार उसी अनुपात में किया जाएगा। महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महिंद्रा लाइफस्पेस में हम औद्योगिक संकुल और एकीकृत शहरों को विकसित करने पर गर्व महसूस करते हैं ।

भारत में रक्षा क्षेत्र में बड़ा विस्तारः एमआरओ क्षेत्र में भारत की तैयारी, घरेलू कंपनियां वैश्विक एरोस्पेस दिग्गजों के साथ मिलकर काम करेंगी

नई दिल्ली। भारत का रक्षा रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में विस्तार के लिए तैयार है। इस क्षेत्र में विश्वस्तरीय एमआरओ केंद्र स्थापित करने के लिए घरेलू कंपनियां वैश्विक एरोस्पेस दिग्गजों के साथ मिलकर काम करेंगी। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियों के निवेश और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) और एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) जैसी भारतीय कंपनियों के साथ क्रियान्वयन में बड़ी सहायता मिलेगी। भारत को एक क्षेत्रीय सैन्य विमानन रखरखाव केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए उद्योग और नीतिगत सुधारों के बल पर अगले पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। भारत में रक्षा प्लेटफॉर्मों की बढ़ती भागीदारी और वैश्विक रक्षा मूल उपकरण विर्माताओं (ओईएम) का समर्थन करने वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को बढ़ावा मिलेगा। लॉकहीड मार्टिन के निदेशक निक स्मिथ ने इस क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में भारत के लिए क्षेत्रीय स्थान साबित होने का दावा किया। एमआरओ क्षेत्र में होने वाले बड़े निवेश की उम्मीद है जो लाखों डॉलर का हो सकता है। भारत को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016, एमआरओ दिशानिर्देश 2021 और जीएसटी दरों में परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि विस्तार में कोई रूकावट न आए। इसमें जो चुनौतियां हैं, उन्हें दूर करके भारत एक गरिमामय रक्षा एमआरओ क्षेत्र बनाने की दिशा में बढ़-चढ़ कर बढ़ रहा है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल- 462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017